

को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख पांच वर्षों की अवधि के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[सं. 7/14/93-बी.ओ.—1]

एम. एस. गोतारामन, अवर सचिव

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 6th October, 1993

S.O. 2219.—In pursuance of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 read with sub-section (2) of Section 6 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby appoints Shri Ashim Chatterjee, IAS (RJ: 60), presently, Adviser, Planning Commission as a Member of the Board for Industrial and Financial Reconstruction for a period of five years from the date of his taking charge.

[No. 7/14/93-B.O.-1]

M. S. SEETHARAMAN, Under Secy.

बीमा-खंड

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2220.—केन्द्रीय सरकार भारतीय जीवन बीमा नियम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के नियमों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम 1985 के नियम 13 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्धारित करती है कि वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों में से प्रत्येक को 1 अप्रैल, 1992 को आरम्भ होने वाली और 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए बोनस के बबले में संदाय उक्त उपनियम में अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसके संयम के 15 प्रतिशत की दर पर किया जाएगा।

[फा. सं. 2 (8)/बीमा-3/91]

सुरेश आनन्द, सहायक बीमा नियंत्रक

INSURANCE DIVISION

New Delhi, the 8th October, 1993

S.O. 2220.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 13 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, the Central Government hereby determine that, subject to the other provisions of the said sub-rule, the payment in lieu of bonus for the period commencing on the 1st day of April, 1992 and ending with the 31st day of March, 1993 to every Class III and Class IV employee shall be at the rate of 15 per cent of his salary.

[F. No. 2(8)/Ins. III/91]

S. ANAND, Asstt. Controller of Insurance

आधिष्य मंत्रालय

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 1993

का. आ. 2221.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (व्यापिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम 1963 (1963 का 22) की धारा 7 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई म्युनिसिपल

कार्पोरेशन को कच्चा मांस (हिमशीत/दुर्लभित) का निर्यात (व्यापिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1992 में अधिपूचित शर्तों के अधीन दिओनार एबोटर से उत्पन्न कच्चा मांस (हिमशीत/दुर्लभित) का निर्यात से पूर्व निरीक्षण करने के लिए एक प्रतिकरण के रूप में मान्यता देना है।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में कच्चा मांस (हिमशीत/दुर्लभित) के निर्यातित प्रभित (i) —

(i) भैंस, शबो कटरों/बछड़े का मांस चार माह से लेकर एक वर्ष तक की आयु के भैंस के कटरों से प्राप्त मांस के शुष्कीत/हिमशीत) द्वारा प्रसंस्कृत तथा कीमा मांस और

(ii) भारतीय बकरा तथा भेड़ कच्चा दुर्लभित/हिमशीत मांस तथा बकरे भेड़ का कीमा मांस और बकरे तथा भेड़ से प्राप्त दुर्लभित/हिमशीत द्वारा प्रसंस्कृत.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फाईल सं. 6/1/92-ई आई एड ई पी]

कुमारी सुमा सुबबन्ना, निदेशक

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 4th October, 1993

S.O. 2221.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Bombay Municipal Corporation as an agency for inspection of Raw Meat (Chilled/Frozen) originating from Deonar abattoir prior to export subject to the conditions notified in the Export of Raw Meat (Frozen/Chilled) (Quality Control and Inspection) Rules, 1992.

Explanation: In this notification Raw Meat (Chilled/Frozen) means:—

(i) Meat and minced meat processed by chilling/quick freezing obtained from Buffalo, Carcasses, veal/Calf meat obtained from buffalo calves of above four months and upto one year of age; and

(ii) Indian goat and sheep raw chilled/frozen meat and minced meat of goat, sheep and processed by chilling/quick freezing obtained from goat and sheep.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 6/1/92-EI&EP]

KUM. SUMA SUBBANNA, Director

कोयला मंत्रालय

श्रावण

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 1993

का. आ. 2222.—कोयला धारक क्षेत्र (घाटन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निकासी गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 2301 तारीख 12 अगस्त 1991 के भारत के राजपत्र भाग खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7 सितम्बर, 1991 से प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न भूमि में वर्णित भूमि में या पूर्ण भूमि पर के अधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन, सही क्रियोगर्भों से मुक्त होकर आर्थिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वैदरने कोल-फील्ड्स लिमिटेड, नागपुर (जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी कम्पनी